डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2021-23

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 1 सितम्बर, 2021, डिस्पेच दिनांक 1 सितम्बर, 2021

| वर्ष 65 | अंक 7 | भोपाल | 1 सितम्बर, 2021 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

किसानों की आय दोगुनी करने के लिए नवीनतम वैज्ञानिक खोजों को खेतों से जोड़ना जरूरी – मुख्यमंत्री श्री चौहान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया एन.के.सी. सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च का शुभारंभ

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि विज्ञान के क्षेत्र में हो रही नवीनतम खोजों और विकसित हो रही तकनीक को किसान के खेत से जोड़ना जरूरी है। एग्री जीनोमिक्स ऐसा वैज्ञानिक क्षेत्र है, जिससे अधिक उपज, कीट प्रतिरोधक क्षमता और फसल की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है। किसानों को अद्यतन वैज्ञानिक जानकारियाँ उपलब्ध कराने में श्री नंदकुमार सिंह चौहान (एन.के.सी.) सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च मील का पत्थर साबित होगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने न्यूक्लियोम इंफॉर्मेटिक्स द्वारा हैदराबाद में स्थापित सेंटर का मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअल शुभारंभ कर रहे थे। केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, सांसद श्री अजय प्रताप सिंह तथा श्री राजेन्द्र गेहलोत, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. के.विजयराघवन, केन्द्रीय पशुपालन सचिव श्री अतुल चतुर्वेदी भी कार्यक्रम में वुर्चअली शामिल हुए।

प्रदेश में स्थापित होगी एशिया की सबसे बड़ी जीनोमिक्स लेब

न्यूक्लियोम इंफॉर्मेटिक्स के प्रबंध संचालक श्री दुष्यंत सिंह बघेल ने बताया कि उनके संस्थान द्वारा इंदौर में एशिया की सबसे बड़ी जीनोमिक्स लेब 165 करोड़ की लागत से स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि लेब की स्थापना में राज्य सरकार हरसंभव सहायता प्रदान करेगी।

डीएनए विधेयक पारित कराने में श्री नंद कुमार चौहान की रही महत्वपूर्ण भूमिका

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निमाड़ क्षेत्र में स्व. श्री नंदकुमार सिंह चौहान द्वारा कृषि के उन्नयन के लिए किए गए प्रयासों का स्मरण करते हुए कहा कि उनके द्वारा संसद में डीएनए विधेयक को पारित कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके परिवार द्वारा कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में देश के किसानों को वैश्विक स्तर की वैज्ञानिक जानकारियाँ उपलब्ध कराने के लिए किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं।

सोयाबीन की फसल सुधार में सहायक होगा एग्री जीनोमिक्स

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में सोयाबीन की फसल लगातार खराब हो रही है। इससे किसान बहुत अधिक प्रभावित हैं। एग्री जीनोमिक्स के उपयोग से सोयाबीन की फसल में सुधार के प्रयोग किए जा सकते हैं। इससे प्रदेश के किसानों को लाभ होगा।

उल्लेखनीय है कि एग्री जीनोमिक्स एक वैज्ञानिक क्षेत्र है, जो फसल सुधार में योगदान दे रहा है। इससे फसल में कीट प्रतिरोधक क्षमता, पौधों के स्ट्रेस टोलरेंस में सुधार कर बेहतर गुणवत्ता की फसलों का अधिक उत्पादन संभव होता है। न्यूक्लियोम इंफॉर्मेटिक्स ने इस क्षेत्र में 2013 में अपनी यात्रा आरंभ की। संस्था द्वारा पशुओं की जीनोम सिक्वेंसिंग का भी कार्य किया जा रहा है।

गडबड़ी करने वालों पर होगी कड़ी कार्यवाही

सहकारी बैकों में सुधार की गतिविधियों का वार्षिक कैलेण्डर बनाये : मंत्री डॉ. भदौरिया

भोपाल। जिला सहकारी बैंकों के संचालन पर नजर रखना सी.ई.ओ. का कार्य है। बैंक में गड़बड़ी करने वालों पर नजर रखें और उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही भी करें। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द मोदी जी ने हाल ही में सहकारिता विभाग का गठन कर गृह मंत्री श्री अमित शाह को सहकारिता विभाग का दायित्व सौंपा है। सहकारिता क्षेत्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। सहकरिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविन्द भदौरिया ने अपेक्स बैंक सभागार में आयोजित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के सी.ई.ओ. की समीक्षा बैठक में उक्त बाते कही।

सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि उज्जैन, खरगोन और रायसेन के बैंकों द्वारा किसानों को ऋण वितरण, वसूली और अन्य बैंकिंग गतिविधियों में दिये गये लक्ष्य से अधिक उपलब्धि प्राप्त की है। इसके विपरीत सतना, मुरैना और दतिया के सहकारी बैंकों की लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत कमजोर स्थिति है। उन्होंने कहा कि जिन बैंकों की कमजोर स्थिति है, ऐसे जिलों के सीईओ इस ओर विशेष ध्यान दें। उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त करने वाले बैंकों के उदाहरण सामने हैं। वह स्वयं चिंतन करें और अपने बैंकों के संचालन की गतिविधियों का विश्लेषण करें। सुधार लाने के लिये हर संभव प्रयास करें। काम में रुचि नहीं लेने वाले बैंकिंग स्टॉफ के संबंध में सहकारिता मंत्री ने कहा कि योग्य और जिम्मेदार को दायित्व दें। परिणाम नहीं देना चाहते ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करें।

सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि बैंकों की सुधार की गतिविधियों का वार्षिक कैलेण्डर बनायें। कैलेण्डर में लक्ष्य तय करें। उन्होंने कहा कि अगली बैठक इसी आधार पर की जायेगी कि किस बैंक ने कितना सुधार किया। अच्छा करने वालों को सराहा जायेगा, लेकिन लापरवाही करने वालों के लिये नरमी नहीं बरती जायेगी।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

विक्रय हेतु विभागीय कार्य मैन्युअल उपलब्ध

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग द्वारा लिये गये निर्णय के परिपालन में राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा निर्मित एवं प्रकाशित ''विभागीय कार्य मैन्युअल'' एक महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ है तथा आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं मध्यप्रदेश की मंशानुसार समस्त संभाग/जिलें तथा प्रदेश की समस्त प्रमुख, शीर्ष/जिला/प्राथमिक, सहकारी सोसायटियों में इसकी कम से कम एक प्रति संधारित की जावें। जिससे प्रकाशित मैन्युअल का लाभ विभागीय अधिकारी/कर्मचारी सहकारी संस्थाओं एवं उनके सदस्यों को हो सकें।

विभागीय कार्य मैन्युअल प्राप्त करने हेतु मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल से सम्पर्क करें। संपर्क सूत्र– 0755–2926160, 2926159, 9755270427 एवं आपके जिले में संचालित जिला सहकारी संघ से सम्पर्क कर सकते है।

''हमारा उद्देश्य सहकारी क्षेत्र में व्यवसाय और जनशक्ति विकास में मान्यता प्राप्त नेतृत्व प्रदान करना है''

जनसहयोग से ही होगा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का नव निर्माण : मुख्यमंत्री श्री चौहान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण किया

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के निर्माण के लिए हर नागरिक को अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करना होगा। प्रदेश के निर्माण के लिए जनता के साथ मिलकर निर्णय लेने के उद्देश्य से प्रदेश में जनभागीदारी मॉडल विकसित किया गया है। प्रदेश में विभिन्न वर्गों की पंचायतों का आयोजन पुन: आरंभ किया जाएगा। जनता के कल्याण की योजनाएँ जनता के साथ मिलकर बनाई जाएंगी और उनका क्रियान्वयन भी जनता के माध्यम से होगा। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का निर्माण जनभागीदारी से किया जाएगा। हमें जनता का सहयोग चाहिए जनसहयोग के बिना अकेली सरकार प्रदेश का नव निर्माण नहीं कर सकती है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के राज्यस्तरीय कार्यक्रम में ध्वजारोहण तथा परेड की सलामी के बाद जनता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण के लिए प्रदेश के नागरिकों को ईमानदारी से अपने कर्तव्य और दायित्वों का पालन करने, बेटियों का सम्मान करने और स्वच्छता अभियान में भाग लेने का संकल्प लेना होगा । हम मिलकर समृद्ध विकसित और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का निर्माण करेंगे। मैं ऐसे मध्यप्रदेश के निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करता हूँ।

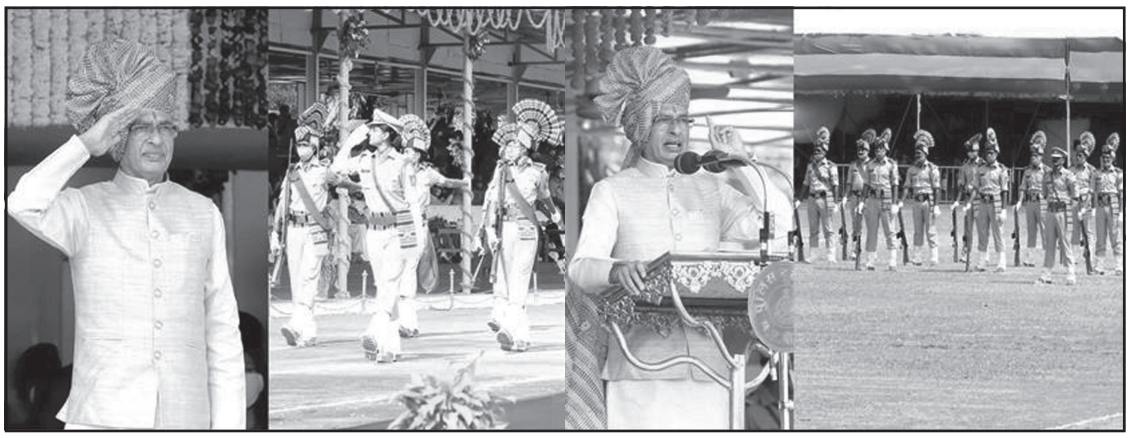

समावेशी विकास और सामाजिक न्याय

हमारी सरकार समावेशी विकास के साथ सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। अन्य पिछड़ा वर्ग का मामला हो, अनुसूचित जाति- जनजाति का कल्याण हो या महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान का विषय हो, राज्य सरकार प्रत्येक क्षेत्र में निरंतर कार्यरत है । अनुसूचित जनजाति के बहनों-भाइयों की भावनाओं, संस्कृति, जीवनमूल्य, परंपरा, रोजगार और शिक्षा के लिए 18 सितम्बर रघुनाथ शाह शंकरशाह के बलिदान दिवस से विशेष अभियान आरंभ किया जाएगा जो 15 नवम्बर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती तक चलेगा। अभियान में कला और संस्कृति की रक्षा, रोजगार के अवसरों की उपलब्धता के साथ-साथ स्वास्थ्य रक्षा और जागरूकता के लिए विशेष गतिविधियां चलाई जाएंगी।

अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण

अनुसूचित जाति वर्ग की सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और शिक्षा की भरपूर चिंता की जाएगी। बजट में इसके लिए 17 हजार 980 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा संविधान में संशोधन कर पिछड़ा वर्ग के बहनों और भाईयों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया है। हमारी सरकार पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पिछड़े वर्गों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक नया आयोग गठित किया जाएगा, । पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए हमारी सरकार कृतसंकल्पित है।

जनभागीदारी मॉडल

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने जन-सहभागिता के साथ निर्णय की पद्धति को मूल मंत्र बनाकर हर स्तर पर समाज को कोविड संबंधी निर्णयों में भागीदार बनाया। नियंत्रण और निर्णय भोपाल से नहीं बल्कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए लिए गए । प्रत्येक जिले में जिला, विकासखण्ड, वार्ड और ग्राम स्तरीय क्राईसिस मैनेजमेन्ट ग्रुप्स का गठन किया गया। मध्यप्रदेश के जन-भागीदारी आधारित कोरोना आपदा प्रबंधन मॉडल को पूरे देश में सराहना मिली है ।

आत्मनिर्भर भारत

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आत्म- निर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में मध्यप्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप के चार स्तंभों-भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य तथा अर्थ व्यवस्था एवं रोजागार के लिए निर्धारित आउटकम्स एवं आउटपुट्स की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है।

अधोसंरचना विकास

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि अधोसंरचना, विकास का आधार है। प्रदेश में वर्ष 2024- 25 तक सिंचाई क्षमता को 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य है। केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना से मध्यप्रदेश को 8 लाख 11 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई, 41 लाख आबादी को पेयजल तथा 103 मेगावाट की विद्युत सुविधा प्राप्त हो सकेगी। प्रदेश में इस वर्ष 2 हजार किलोमीटर लम्बाई की सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन, ढाई हजार किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण और 80 बड़े पुल एवं रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इन कार्यों पर 5 हजार 530 करोड़ रुपए खर्च किये जायेंगे।

हर घर तक नल द्वारा पेयजल

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने हर गाँव में घर-घर तक पीने का शुद्ध जल पहुँचाने के लिए जल जीवन मिशन प्रारंभ किया। इस मिशन के अंतर्गत हमने वर्ष 2023 तक प्रदेश के कुल एक करोड़ 22 लाख ग्रामीण परिवारों के हर घर में नल से जल पहुंचाने का संकल्प लिया है।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

युवाओं, महिलाओं, किसानों और खिलाड़ियों पर पीएम का फोकस, 75वें स्वतंत्रता दिवस पर कई बड़े एलान

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लालकिले की प्राचीर से लगातार आठवीं बार देश को संबोधित किया । उन्होंने कई बड़े एलान किए । संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री का विशेष फोकस युवाओं, महिलाओं, किसानों और खिलाड़ियों पर रहा। प्रधानमंत्री ने युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए सौ लाख करोड़ की गति शक्ति योजना शुरू करने की बड़ी घोषणा की । उन्होंने देश भर के सैनिक स्कूलों के दरवाजे बेटियों के लिए भी खोल देने का बड़ा एलान किया । उन्होंने देशभर में आवागमन की सुविधा बढ़ाने के लिए 75 वंदेभारत ट्रेनों की शुरुआत भी किए जाने की घोषणा की।

प्रधानमंत्री ने 80 फीसदी छोटे किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में सरकार का फोकस छोटे किसानों की सामूहिक शक्ति बढ़ाने पर होगा। प्रधानमंत्री ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के सम्मान

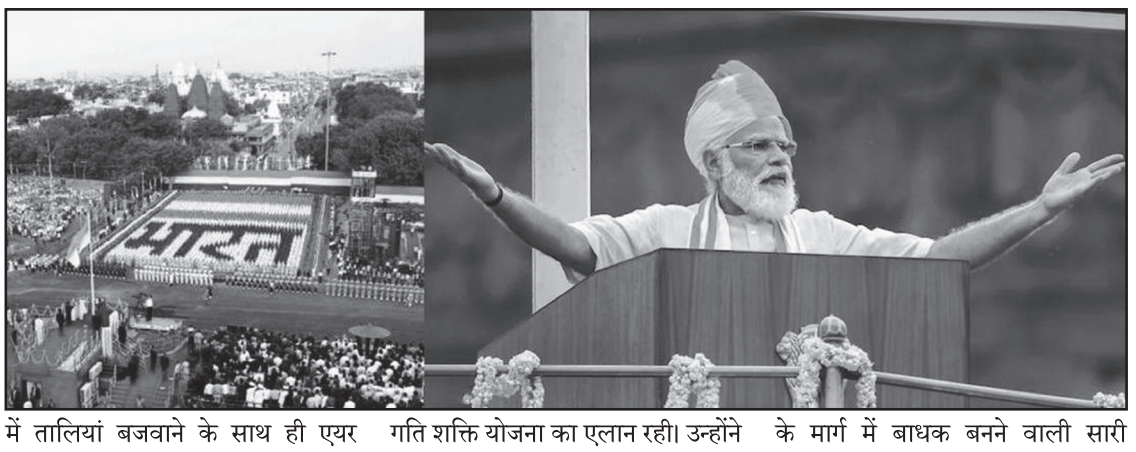

में तालियां बजवाने के साथ ही एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करते हुए दुश्मनों को कड़ा संदेश देने की भी कोशिश की । प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास के साथ ही अब सबका प्रयास ही हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में मददगार बनेगा।

गति शक्ति योजना बदलेगी युवाओं की किस्मत

प्रधानमंत्री के संबोधन की सबसे महत्वपूर्ण बात सौ लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति योजना का एलान रही। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जल्द ही देशवासियों के समक्ष गति शक्ति योजना का मास्टर प्लान रखा जाएगा। यह देश के लिए एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना साबित होगी क्योंकि इसके जरिए लाखों नौजवानों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इस योजना से देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलने के साथ ही नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूती मिलेगी। इस योजना के जरिए विकास के मार्ग में बाधक बनने वाली सारी कठिनाइयों को खत्म किया जाएगा। देश के लोगों के ट्रेवल टाइम में कमी आएगी और इसके साथ ही उत्पादकों को भी भारी मदद मिलेगी। हालांकि प्रधानमंत्री ने अभी इस योजना के मुख्य बिंदुओं का खुलासा नहीं किया है मगर माना जा रहा है कि सरकार की ओर से जल्द ही इसका पूरा खाका पेश किया जाएगा।

बेटियों के लिए खोले सैनिक स्कूलों के दरवाजे

प्रधानमंत्री ने देश के विकास में बेटियों के योगदान की चर्चा करते हुए कहा कि आज कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां हमारी बेटियां बढ़-चढ़कर अपना प्रभाव नहीं दिखा रही हैं। उन्होंने महिलाओं और बेटियों को सम्मान देने के लिए शासन-प्रशासन, पुलिस और नागरिकों से भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की अपील की।

प्रधानमंत्री ने देश भर के सैनिक की स्कूलों के दरवाजे बेटियों के लिए खोल देने का भी महत्वपूर्ण एलान किया। उन्होंने कहा कि मुझे काफी दिनों से देशभर की बेटियों की ओर से इस बाबत अनुरोध मिल रहे थे और अब उनके अनुरोध को पूरा करने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिजोरम के सैनिक स्कूल में बेटियों को प्रवेश देने का प्रयोग सफल होने के बाद अब सरकार ने देश भर के सैनिक स्कूलों में बेटियों को भी प्रवेश देने का फैसला किया है।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 69 फसलों की 1017 किस्में विकसित

नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (एनएआरएस), जिसमें भाकृअप संस्थान और राज्य/ केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय सम्मिलित हैं, फील्ड और बागवानी फसलों की नई उच्च पैदावार वाली फसल किस्मों का विकास किया जा रहा है। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि गत तीन वर्षों (2018-2020) और वर्तमान वर्ष के दौरान 69 फील्ड फसलों की 1017 किसमें और 58 बागवानी फसलों की 206 किस्में विकसित की गई हैं।

भाकृअप के पास विभिन्न संस्थानों द्वारा समन्वित, अनुसंधान परियोजनाओं (एआईसीआरपी)/ नेटवर्क परियोजनाओं (एआईएनपी) का एक मजबूत नेटवर्क है, जो फील्ड और बागवानी की नई फसल किस्मों के विकास के लिए विभिन्न केन्द्रीय और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में कार्यरत हैं। सम्पूर्ण देश में 1017 स्थानों पर 50 एसएयू/ सीएयू/डीयू और 55 भाकृअप संस्थानों के माध्यम से फील्ड और बागवानी फसलों की 44 एआईसीआरपी/ एआईएनपी चल रही हैं।

भाकृअप ने इन अनुसंधान संस्थानों/ विश्वविद्यालयों के लिए वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान रू. 3340.32 करोड़ स्वीकृत किए हैं जिसमें से वर्ष 2020-21 तक रु. 2420.32 करोड़ की राशि का उपयोग किया है।

कृषि की समस्याओं पर फोकस करें वैज्ञानिक – उपराष्ट्रपति

बेंगलुरु। उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने वैज्ञानिकों से मानव जाति के सामने आने वाली जलवायु परिवर्तन से लेकर कृषि से लेकर स्वास्थ्य और चिकित्सो जैसी चुनौतियों को हल करने के लिए अनूठे समाधान प्रस्तुत करने की अपील की। बेंगलुरु में जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र (जेएनसीएएसआर) में वैज्ञानिकों और छात्रों को संबोधित करते हुए, उपराष्ट्रपति ने वैज्ञानिकों से उत्कृष्टता हासिल करने और लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए नवोन्मेषण के लिए प्रयास करने की अपील की। उन्होंने दोहराया "विज्ञान का उद्देश्य लोगों के जीवन को सुखी, स्वस्थ और आरामदायक बनाना है।" उपराष्ट्रपति ने कृषि को 'देश की मूल संस्कृति' बताते हुए इच्छाअ जताई कि वैज्ञानिकों को अपना ध्यान कृषक समुदाय के सामने आने वाले मुद्दों पर केंद्रित करना चाहिए।

प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार, 2020 के लिए नामांकित किए गए प्रख्यात वैज्ञानिक, प्रो. सी.एन.आर. राव को बधाई देते हुए, उन्होंने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में युवा वैज्ञानिकों को प्रेरित करने के लिए उनकी सराहना की।

कर्नाटक के राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत, कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई, कर्नाटक के उच्चतर शिक्षा, आईटी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और कौशल विकास मंत्री श्री सी.एन. अश्वथ नारायण, प्रख्यात वैज्ञानिक प्रो. सी.एन.आर. राव और जेएनसीएएसआर के अध्यक्ष प्रो. जी.यू. कुलकर्णी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

जिला संघो के आर्थिक सुदृढ़ीकरण पर प्रशिक्षण सपन्न

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल में सहकारी शिक्षण प्रशिक्षण की योजना एवं जिला संघो की आर्थिक सक्षमता पर प्रशिक्षण दिनांक 27.08.2021 को प्रदान किया गया। जिसमें श्री श्रीकुमार जोशी द्वारा जिला सहकारी संघ का प्रमुख कार्य पर जानकारी दी गई। श्री ऋतुराज रंजन प्रबंध संचालक, राज्य संघ द्वारा जिला स्तर पर संचालित सहकारी शिक्षा- प्रशिक्षण योजना की यह विस्तृत जानकारी दी गई, श्रीमती रशिम गोलिया द्वारा व्यक्तित्व विकास, समय प्रबंधन, तनाव प्रबंधन पर प्रशिक्षण दिया गया एवं श्री संजय कुमार सिंह, राज्य सहकारी शिक्षा अधिकारी द्वारा सहकारी प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबंधन व नवाचार पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम का समन्वय श्री संतोष येडे , राज्य समन्वयक , श्री ए.के. जोशी पूर्व प्राचार्य द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम मे श्री विक्रम मजूमदार , श्री विनोद कुशवाह , श्री प्रवीण कुशवाह का विशेष सहयोग रहा |

वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 16000 करोड़ का बजट

नई दिल्ली। सरकार देश में किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार कृषि के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हुए किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है। यह जानकारी केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने सांसद सर्वश्री गोपाल चिन्नाया शेट्टी, प्रभुभाई नागरभाई वसावा एवं श्रीमती रीती पाठक के सवाल के जवाब में लोकसभा में दी। श्री तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) घटक सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देता है, बीज और रोपण सामग्री उप मिशन (एसएमएसपी) गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन एवं वितरण के लिए बुनियादी ढांचे को विकसित और मजबूत करने पर केंद्रित है तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) किसानों द्वारा देय कम प्रीमियम दर पर प्राकृतिक जोखिमों के साथ बुवाई से लेकर फसलोपरांत नुकसान तक फसल बीमा प्रदान करता है। कृषि मंत्री ने बताया कि इन योजनाओं के लिए इस वर्ष 2021-22 में फसल बीमा के लिए 16000 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत-पर ड्राप मोर क्रॉप के लिए 4000 करोड़ रुपये एवं बीज और रोपण सामग्री उपमिशन (एसएसपी) के लिए 448 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

श्री तोमर ने बताया कि सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर 22 अधिसूचित फसलों का एमएसपी और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) निर्धारित करती है। कृषि मंत्री ने बताया कि विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाएं सभी किसानों पर लागू होती हैं, चाहे वे किसी भी आयु वर्ग के हों। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-20 में, सरकार ने 60 वर्ष की वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक स्वैच्छिक पेंशन योजना, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएमकेएमवाई) की भी शुरूआत की है।

कृषि क्षेत्र की चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने में किसान सक्षम – श्री तोमर

विश्व के दूसरे सबसे बड़े नवीनीकृत जीन बैंक का लोकार्पण

नई दिल्ली। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो , पूसा, नई दिल्ली में विश्व के दूसरे सबसे बड़े नवीनीकृत-अत्याधुनिक राष्ट्रीय जीन बैंक का लोकार्पण केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र के समक्ष विद्यमान चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उन पर विजयी प्राप्त करने में भारत के किसान पूरी तरह सक्षम है, हमारे किसान बिना किसी बड़ी शैक्षणिक डिग्री के भी कुशल मानव संसाधन है।

श्री तोमर ने प्रो. बी.पी. पाल, प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन और प्रो. हरभजन सिंह जैसे दूरदर्शी विशेषज्ञों की सेवाओं को सराहते हुए कहा कि इन्होंने देश में स्वदेशी फसलों की विविधता संरक्षण के लिए मजबूत नींव रखी थी। हमारा गौरवशाली अतीत रहा है, उसे पढ़कर देश की प्रगति के लिए सभी को भविष्य के प्रति जिम्मेदारी के भाव के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। यह नवीनीकृत-अत्याधुनिक राष्ट्रीय जीन बैंक इसी दिशा में एक सशक्त हस्ताक्षर है।

कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने कहा कि जर्मप्लाज्म के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं सहित नवीनीकृत जीन बैंक से कृषि-किसानों को काफी फायदा होगा। सरकार सकारात्मक सोच से काम कर रही है। प्रधानमंत्री का लक्ष्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का है, सरकार इस दिशा में हरसंभव प्रयास कर रही है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. त्रिलोचन महापात्र ने स्वागत भाषण देते हुए ब्यूरो की गतिविधियां व प्रगति बताई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने ब्यूरो के कुछ प्रकाशनों का विमोचन किया तथा पीजीआर मैप एप लांच किया। जीन बैंक के आधुनिकीकरण के लिए, ब्यूरो के हाल ही में सेवानिवृत निदेशक श्री कुलदीप सिंह की सेवाओं को सराहा गया। आईसीएआर के उप महानिदेशक डॉ. तिलक राज शर्मा ने आभार माना। कार्यवाहक निदेशक श्री अशोक कुमार व वीना गुप्ता सहित अन्य स्टाफ भी मौजूद था

पादप आनुवंशिक संसाधनों (पीजीआर) के बीजों को भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करने हेतु वर्ष 1996 में स्थापित नेशनल जीन बैंक में बीज के रूप में लगभग 10 लाख जर्मप्लाज्म को संरक्षित करने की क्षमता है। वर्तमान में 4.52 लाख परिग्रहण का संरक्षण कर रहा है, जिसमें 2.7 लाख भारतीय जननद्रव्य है व शेष अन्य देशों से आयात किए हैं। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, दिल्ली मुख्यालय व देश में 10 क्षेत्रीय स्टेशनों के माध्यम से इन-सीटू और एक्स-सीटू जर्मप्लाज्म संरक्षण की आवश्यकता को पूरा कर रहा है।

भारत की अगुवाई में मनाया जाएगा पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष

नई दिल्ली। वर्ष 2023 में भारत की अगुवाई में दुनियाभर में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। इस संबंध में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक हुई । इसमें पोषक अनाज को बढ़ावा देने के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार द्वारा पहले से भी पोषक अनाज संबंधी योजनाएं-कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

श्री तोमर ने बताया कि भारत में खेती-किसानी व किसानों को समृद्ध करने के दृष्टिकोण के साथ, प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रस्ताव पर, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फैसला किया है कि वर्ष 2023 में भारत के प्रायोजन में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाया जाएगा। इसकी घोषणा के लिए भारत द्वारा वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) को पत्र भेजा गया था, जिसके बाद एफएओ की कृषि संबंधी समिति व परिषद द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार करने तथा एफएओ के 41वें सत्र में प्रस्ताव का समर्थन किए जाने सहित अन्य प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह वर्ष मनाने का निर्णय लिया गया है। श्री तोमर ने बताया कि इसके माध्यम से खाद्य सुरक्षा व पोषण के लिए पोषक अनाज के योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना उद्देश्य है। खान-पान व स्वास्थ्य की बदलती स्थितियों के बीच पोषक अनाज का और अधिक महत्व है, जो वर्षों पहले व्यापक उपयोग होता रहा।

केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने बताया कि मिलेट्स के विकास के लिए भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए है। 2018 में इसका राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया, साथ ही एक विशिष्ट पहचान प्रदान करने के लिए कदन्नों को पोषक अनाज के रूप में अधिसूचित किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत उप-मिशन प्रारंभ किया गया, वहीं कदन्न मूल्य श्रृंखला में राज्य सरकारों व हितधारकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए है। देश में 18 बीज उत्पादन केंद्र व 22 बीज हब स्थापित किए गए हैं। सरकार द्वारा क्लस्टर व अग्रेखित प्रदर्शनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, मूल्य संवर्धित उत्पादों को विकसित करने के लिए मिलेट्स के तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने, पोषण मिशन अभियान में मिलेट्स को शामिल करने जैसे कदम भी इसमें शामिल है। मिलेट्स के अनेक कृषक उत्पादन संगठन (एफपीओ) भी स्थापित किए गए हैं, साथ ही भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान (IIMR) ने खेत से थाली तक मिलेट्स पर संपूर्ण मूल्य श्रृंखला विकसित की है।

भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का सकारात्मक प्रभाव हुआ है, जिससे वर्ष 2017-18 में मिलेट्स का जो उत्पादन 164 लाख टन था, वह वर्ष 2020-21 में बढ़कर 176 लाख टन हो गया है और वर्ष 2017-18 में उत्पादकता 1163 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर 1239 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है। मिलेट्स का निर्यात वर्ष 2017 में 21.98 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2020 में बढ़कर 24.73 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। 96 अधिक उपज देने वाली, रोग प्रतिरोधी, जिसमें 10 पोषक-अनाज फसलें व 3 जैव शक्तियुक्त किस्में शामिल हैं, का विमोचन किया गया है। नई अधिक उपज देने वाली किस्मों और संकर क़िस्मों के गुणवत्ता वाले बीज की उपलब्धता में वृद्धि हुई है और वर्ष 2020-21 में 5780 क्विंटल बीज उत्पादित हुए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाने के लिए की जाने वाली गतिविधियों के प्रस्तावों पर आज बैठक में विस्तृत चर्चा की गई। भारतवर्ष के साथ ही अन्य देशों में भी अनेक आयोजन किए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी के मुख्य आतिथ्य में इसका आगाज होगा। 2023 में सालभर कार्यक्रमों का सिलसिला चलेगा और इससे पहले भी अनेक कार्यक्रम प्रारंभिक रूप से किए जाएंगे। इसमें राज्य सरकारों, सभी जिलों के स्थानीय प्रशासन, नगरीय निकायों तथा देशभर के सांसदों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाएगा। बैठक में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी, कृषि सचिव श्री संजय अग्रवाल, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डा. त्रिलोचन महापात्र, कृषि मंत्रालय के अपर सचिव श्री अभिलक्ष लेखी व श्री विवेक अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय कृषि आयुक्त डा. एस.के. मल्होत्रा ने प्रेजेन्टेशन दिया।

भारत का मिलेट्स उत्पादन एशिया का 80 प्रतिशत- पोषक अनाज (मिलेट्स) जलवायु प्रतिरोधक क्षमता वाली फसलें हैं, जो 131 देशों में उगाई जाती हैं। यह भोजन के लिए उगाई जाने वाली अनाज की प्रथम फसल है, जिसके सिंधु सभ्यता में पाए गए सबसे पहले प्रमाण 3000 ईसा पूर्व के हैं। एशिया और अफ्रीका में लगभग 59 करोड़ लोगों के लिए यह पारंपरिक भोजन है। इसमें बाजरा, ज्वार, रागी/मंडुवा, कांगनी, कोदो, कुटकी, चीना, सावां, ब्राउनटाप मिलेट, टेफ्फ मिलेट, फोनीओ मिलेट शामिल है। भारत में लगभग 140 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग पौने दो सौ लाख टन मिलेट्स का उत्पादन होता है, वहीं वैश्विक परिदृश्य 717 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में लगभग 863 लाख टन मिलेट्स उत्पादन का है।

भारत का मिलेट्स उत्पादन एशिया का 80 प्रतिशत एवं वैश्विक उत्पादन का 20 प्रतिशत है। देश में मुख्य रूप से आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में मिलेट्स की खेती होती है।

खाद्य तेल के उत्पादन बढाने के लिए 11,040 करोड़ रुपये का एक राष्ट्रीय मिशन का ऐलान

नई दिल्ली। देश में खाने के तेल की कीमतों पर जल्द ही ब्रेक लग सकता है। मोदी सरकार ने खाद्य तेल के आयात पर निर्भरता कम करने तथा इसके उत्पादन बढाने के लिए 11,040 करोड़ रुपये का एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करने का ऐलान किया है। कैबिनेट ने 11,040 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय खाद्य तेल-पाम तेल मिशन को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में कृषि मंत्रालय के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार ने दो निर्णय लिए हैं, एक पाम तेल के कच्चे माल का दाम केंद्र सरकार तय करेगी। दूसरा अगर बाजार में उतार-चढ़ाव की वजह से किसान की फसल का मूल्य कम होने पर केंद्र सरकार DBT के माध्यम से किसानों का नुकसान पूरा करेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खेती के सामग्री में जो पहले राशि दी जाती थी, उस राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में लोग इंडस्ट्री लगा सके, इसके लिए इंडस्ट्री को भी 5 करोड़ रु. की सहायता देने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने पाम की खेती पर किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी और रोपण सामग्री पर सहायता बढ़ाने का भी फैसला लिया है।

भारत घरेलू तेल की मांग को पूरा करने के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर करता है। देश में सालाना 2.4 करोड़ टन खाद्य तेल का उत्पादन होता है। बाकी मांग को पूरा करने के लिए दुनिया से बाकी आयात करता है। भारत इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम तेल, ब्राजील और अर्जेंटीना से सोया तेल और मुख्य रूप से रूस एवं यूक्रेन से सूरजमुखी तेल का आयात करता है। कुल आयात में पाम तेल की हिस्सेदारी करीब 55 फीसदी है।

बाढ़ प्रभावित किसानों के नुकसान की भरपाई सरकार करेगी

52 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खातों में पहुंचाई

भोपाल । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ग्वालियर-चंबल संभाग के जिलों और विदिशा जिले के बाढ़ प्रभावितों को राहत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जायेगी। हर बाढ़ पीड़ित को संकट से निकालने में सहायता देंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश सरकार अब तक बाढ़ प्रभावित परिवारों के खातों में 52 करोड़ रूपए से अधिक राशि पहुँचा चुकी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्योपुर जिला मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाढ़ प्रभावितों के खातों में ऑनलाइन 23 करोड़ 19 लाख रूपये से अधिक की राशि का अंतरण कर बाढ़ प्रभावित लोगों से वर्चुअली संवाद किया। केन्द्रीय कृषि विकास एवं किसान-कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर भी मौजूद थे।

सबको संकट से पार ले जायेंगे

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित लोगों से संवाद करते हुए कहा कि तात्कालिक तौर पर बाढ़ प्रभावित परिवारों को 6 हजार रूपए, 50 किलो अनाज और रोजमर्रा की जरूरतों का अन्य सामान मुहैया कराया गया है। साथ ही सर्वे के आधार पर आर्थिक राहत भी खातों में पहुँचाई गई है।

सहायता के लिए तीन सूत्री रणनीति

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुँचाने के लिये सरकार ने 12 विभागों को जोडक़र टास्क फोर्स बनाया है। उन्होंने कहा तात्कालिक राहत के साथ मकान बनाने के लिये एक लाख 20 हजार, दुधारू पशु की मृत्यु पर 30 हजार, बैल की मृत्यु पर 25 हजार, बकरा-बकरी इत्यादि की मृत्यु पर 3 हजार रूपए की आर्थिक राहत दी जा रही है। साथ ही फसल नुकसान की भरपाई भी सरकार आरबीसी के प्रावधानों के तहत करेगी ।

खेतों में जमा सिल्ट सरकार हटवायेगी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बाढ़ प्रभावित लोगों को यह भी भरोसा दिलाया कि जिन किसानों के खेतों में बाढ़ की वजह से सिल्ट जमा हो गई है उसे हटवाने का काम भी सरकार अपने खर्चे पर करेगी।

सरकार ने मदद पहुँचाने की हरसंभव कोशिश की

केन्द्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रकृति पर किसी का जोर नहीं चलता। पर हर लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व है कि आपदा के समय प्रभावित लोगों तक जल्द से जल्द हर संभव मदद पहुँचाए।

इस पैमाने पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार पूरी तरह खरी उतरी है। केन्द्र सरकार ने भी इसमें हरसंभव मदद की है। समाज ने भी इस आपदा से निपटने में हाथ बँटाया है।

केन्द्रीय दल ने की भेंट

मध्यप्रदेश के बाढ़ से प्रभावित हुए जिलों का अवलोकन करने आए केंद्रीय दल के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में भेंट की और विवरण प्राप्त किया। इस अवसर पर राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत एवं छह सदस्यीय केन्द्रीय दल में श्री सुनील कुमार वर्णवाल संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय, श्री अभय कुमार उप आर्थिक सलाहकार वित्त मंत्रालय, श्री ए.के. तिवारी डायरेक्टर डीपीडी कृषि मंत्रालय,आदि शामिल थे। केंद्रीय दल ने बताया कि दो समूह में दल के सदस्यों ने तीन-तीन जिलों में भ्रमण कर स्थितियों का जायजा लिया। प्रथम दल के तीन सदस्य ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी और द्वितीय दल के तीन सदस्य श्योपुर और मुरैना क्षेत्र के भ्रमण के बाद क्षति का अवलोकन कर चुके हैं। दल ने बताया कि इन क्षेत्रों में काफी क्षति हुई है।

कृषि संबद्ध व्यवसायों को भी अपनायें कृषक बँधु - कृषि मंत्री श्री पटेल

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद क्षेत्रीय समिति की बैठक में ऑनलाइन हुए सम्मिलित

भोपाल : खेती को लाभ का धँधा बनाने के लिये जरूरी है कि कृषक बँधु कृषि संबद्ध अन्य व्यवसायों को भी अपनायें। इससे निश्चित ही किसानों को लाभ मिलेगा। नवीन तकनीकों को अपनाने से कम लागत में अधिक उत्पादन से ज्यादा मुनाफा प्राप्त करना आसान होगा। किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने गत दिवस भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की क्षेत्रीय समिति की 7वीं बैठक को ऑनलाइन संबोधित करते हुए यह बातें कहीं। कृषि अनुसंधान परिषद के उक्त वेबीनार में केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, केन्द्रीय पशुपालन मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला, केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री द्वय श्री कैलाश चौधरी एवं सुश्री शोभा करंदलाजे, महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद डॉ. त्रिलोचन महापात्रा एवं मध्यप्रदेश के ग्वालियर और जबलपुर के कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति भी सम्मिलित थे।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि मध्यप्रदेश के कृषकों ने कोरोना काल में भी जब सारे कार्य बंद थे, तब कृषि कार्य किया। साथ ही अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान किया। कृषकों के अथक परिश्रम से ही प्रदेश को निरंतर कृषि कर्मण अवार्ड मिलता रहा है। श्री पटेल ने कृषकों के आर्थिक सशक्तिकरण और खेती को लाभ का धँधा बनाने के लिये कृषि की बेहतरी के लिये समुचित कदम उठाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि सोयाबीन स्टेट का दर्जा प्राप्त होने के बाद सोयाबीन उत्पादन में कमी होना चिंताजनक है। श्री पटेल ने सोयाबीन के उत्पादन को बढ़ाने के लिये पुरानी किस्मों के स्थान पर नई किस्मों को विकसित करने का आव्हान कृषि वैज्ञानिकों से किया।

श्री पटेल ने कहा कि खेती को लाभ का धँधा बनाने के लिये कृषि वैज्ञानिकों को महती भूमिका निभानी होगी। इसके लिये नई उन्नत किस्मों का विकास करना होगा। सामान्य कृषकों को भी जैविक खेती के लिये प्रोत्साहित करना होगा, जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति को क्षरण से बचाते हुए निरंतर उत्पादन को बढ़ाया जा सके। श्री पटेल ने बताया कि प्रदेश में 11 लाख हेक्टेयर भूमि में जैविक खेती की जा रही है। उन्होंने कहा कि जैविक खेती के लिये प्रदेश के 89 आदिम-जाति विकासखण्डों के छोटे और मझौले किसानों को प्रोत्साहित कर जैविक खेती के क्षेत्र को और अधिक बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, जिससे किसानों को लाभ भी होगा।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में खेती को लाभ का धँधा बनाने के लिये किसानों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने प्रदेश के किसानों की ओर से केन्द्र सरकार द्वारा कृषकों के हित में लिये जा रहे निर्णयों के लिये आभार व्यक्त किया।

हर वर्ग की भागीदारी से बिछेगा प्रदेश में उद्योगों का जाल : मुख्यमंत्री श्री चौहान

जो सबसे पीछे और नीचे हैं उनका उत्थान हमारी प्राथमिकता ● नए उद्यमियों को अवसर देने उद्योग नीति में होंगे व्यवहारिक बदलाव

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के लिए राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों का जाल बिछाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा प्रयास है कि उद्यमशीलता की इस गतिविधि में समाज के हर वर्ग की बराबर की भागीदारी हो। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने देश को संविधान देकर शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो का मंत्र दिया। राज्य सरकार जो सबसे पीछे और नीचे हैं उनका संवैधानिक अधिकार, सुरक्षा और उन्हें प्रगति के सभी अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृत-संकल्पित है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान दलित इंडियन चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज (डिक्की) की नेशनल काउंसिल मीट को संबोधित कर रहे थे । होटल पलाश में आयोजित मीट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओमप्रकाश सकलेचा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह, डिक्की के संस्थापक पद्मश्री डॉ. मिलिंद काम्बले, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रवि कुमार नारा, ट्रायफेड के प्रबंध संचालक श्री प्रवीर कृष्ण,डिक्की के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अनिल सिरवैया उपस्थित थे। कार्यक्रम में केन्द्र तथा राज्य की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में असीम संभावनाएँ हैं। खनिज, वन संपदा, कृषि उत्पादन, पर्यटन के क्षेत्र में उद्यमिता की व्यापक संभावनाएँ विद्यमान हैं। युवा वर्ग को उद्यमिता के लिए प्रेरित करने नीतियों को अधिक व्यवहारिक और सहयोगी बनाने के उद्देश्य से उद्योग नीतियों में आवश्यक सुधार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में ज्ञानोदय विद्यालय तथा एकलव्य विद्यालय के माध्यम से अनुसूचित जाति-जनजाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में वनोपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था की गई है। देवारण्य योजना के माध्यम से जनजातीय बहुल क्षेत्रों में वहाँ के ईको सिस्टम के अनुसार परम्परागत औषधीय और सुगंधित पौधों को ऊगाने से लेकर उनकी प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और विक्रय की सम्पूर्ण वैल्यू चेन विकसित की जा रही है।

युवाओं को उद्यमी के रूप में विकसित करना आवश्यक

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश के मनोहर श्याम की पेंटिंग और डिण्डौरी की रेखा पेंदराम द्वारा कोदो-कुटकी की ब्रांडिंग कर अपने उत्पाद को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए की गई पहल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि युवाओं को सहायता ही पर्याप्त नहीं है। उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन और प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर उद्यमी के रूप में विकसित करना आवश्यक है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।

जनजातीय युवाओं को उत्पादों की प्रोसेसिंग से जोड़ा जाए

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि खनिज सम्पदा के दोहन, वन सम्पदा के संग्रहण और कृषि उत्पादन में प्रदेश की जनजातियों का योगदान है। जनजातीय युवाओं को सहयोग, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन उपलब्ध कराकर खनिज, वन और कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग से जोड़ना आवश्यक है।

प्रत्येक जिले में होगी उद्यमिता पर कार्यशाला

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में उद्यमिता पर कार्यशाला आयोजित की जा रही है। हमारा उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापित करने के लिए युवाओं को जिला स्तर पर आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम को ट्रायफेड के प्रबंध संचालक श्री प्रवीर कृष्ण, डिक्की के संस्थापक डॉ. मिलिंद काम्बले और प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल सिरवैया ने भी संबोधित किया।

(पृष्ठ 2 का शेष)

युवाओं, महिलाओं, किसानों और खिलाड़ियों....

ग्रामीण महिलाओं के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म

प्रधानमंत्री ने ग्रामीण महिलाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हमारी करोड़ों बहनें एक से बढ़कर एक उत्पाद बनाने में माहिर हैं। ग्रामीण महिलाओं के इन उत्पादों को बड़ा बाजार मुहैया कराने के लिए सरकार की ओर से जल्द ही ई-कॉमर्स प्लेटफार्म तैयार किया जाएगा। इस प्लेटफार्म के जरिए इन महिलाओं के उत्पाद देश के विभिन्न हिस्सों में ही नहीं बल्कि विदेशी बाजार तक भी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की असली भावना यही है कि हमें सभी के सामर्थ्य को उचित अवसर और प्लेटफार्म प्रदान करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें सरकारी योजनाओं की गति बढ़ाने में कामयाबी मिली है। पहले की तुलना में योजनाओं में तेजी तो आई है मगर बात यही पूरी नहीं हो जाती क्योंकि अभी हमें पूर्णता हासिल करनी है।

अब छोटे किसानों पर होगा सरकार का फोकस

प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि हम ग्रामीण इलाकों के किसानों को देखें तो किसानों की जमीन लगातार छोटी होती जा रही है। देश में 80 फ़ीसदी किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। सरकार की योजना इन छोटे किसानों को आगे बढ़ाने की है। देश में किसानों के लिए बनाई गई नीतियों में छोटे किसानों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया मगर आने वाले दिनों में हमारा फोकस इन छोटे किसानों पर होगा।

हमारा सपना इन छोटे किसानों को देश की शान बनाना है और आने वाले दिनों में सरकार इन छोटे किसानों की शक्ति बढ़ाने पर जोर देगी। उन्होंने छोटे किसानों को नई सुविधाएं मुहैया कराने का भी संकेत दिया।

(पृष्ठ 2 का शेष)

जनसहयोग से ही होगा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश....

किसानों का कल्याण

किसान कल्याण योजना में वर्ष 2021-22 में प्रथम किस्त के रूप में 75 लाख किसानों को लगभग डेढ़ हजार करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लगभग 81 लाख किसानों को अब तक लगभग 11 हजार करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया जा चुका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लगभग 9 हजार करोड़ रुपए से अधिक की दावा राशि का 45 लाख 40 हजार से जयादा पात्र किसानों को भुगतान किया जा चुका है। वर्ष 2020-21 में प्राथमिक सहकारी साख समितियों के माध्यम से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर लगभग 15 हजार करोड़ रुपए का फसल ऋण वितरित किया गया है। इस साल 17 लाख 94 हजार किसानों से लगभग 130 लाख मीट्रिक टन गेहूँ, चना एवं मसूर का उपार्जन कर लगभग 26 हजार करोड़ रुपए का उन्हें भुगतान किया गया है।

पूंजी निवेश में वृद्धि

सकारात्मक निवेश वातावरण के कारण प्रदेश में पूँजी निवेश में वृद्धि हुई है। व्यापार को सरल बनाने की दिशा में हम तेजी से कार्य कर रहे हैं। एक जिला- एक उत्पाद योजना के अंतर्गत सभी जिलों के 64 विशिष्ट उत्पादों का चयन कर लिया गया है। लोकल को वोकल बनाने की दिशा में यह एक सार्थक कदम है। प्रदेश में सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्योगों के क्लस्टर आधारित विस्तार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रदेश में फर्नीचर, खिलौना, टेक्सटाईल,फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग आदि विभिन्न क्षेत्रों के 13 क्लस्टर विकसित किए जायेंगे।

पथ व्यवसाईयों, मजदूरों को रोजगार

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोविड-19 के कठिन दौर में पथ पर व्यवसाय करने वाले भाई-बहन प्रभावित हुए हैं। उनकी आजीविका संरक्षण की पीएम स्व-निधि योजना के क्रियान्वयन में हम देश में द्वितीय हैं। प्रदेश के 12 लाख शहरी और ग्रामीण पथ विक्रताओं को कोविड की दूसरी लहर के दौरान प्रति विक्रेता 1 हजार रुपए के मान से लगभग 120 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता दी गई। कोरोना संक्रमण के दौरान एक करोड़ 6 लाख से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को मनरेगा से रोज़गार दिलाकर हम देश में अग्रणी रहे हैं।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत एक करोड़ 15 लाख पात्र परिवारों के लगभग 5 करोड़ हितग्राहियों को 25 हजार से अधिक राशन दुकानों से नि:शुल्क खाद्यान्न थैले में देने का शुभारंभ प्रधानमंत्रीजी द्वारा किया गया।

स्व-सहायता समूहों एवं महिलाओं का सशक्तीकरण

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि महिला सशक्तिकरण हमारा संकल्प है। लाड़ली लक्ष्मी योजना में बिटिया के जन्म के समय 2 हज़ार रुपये उसके खाते में डाले जाएंगे। लाड़ली लक्ष्मी बेटियां जैसे ही कॉलेज में प्रवेश करेंगी उन्हें 20 हज़ार रुपय प्रदान किए जाएंगे। बेटियों की नि:शुल्क उच्च शिक्षा की व्यवस्था रहेगी। पिछले 16 माह में हमने 1 लाख 15 हजार से अधिक स्व-सहायता समूहों को लगभग डेढ़ हजार करोड़ रुपए बैंक लोन के रूप में उपलब्ध कराये हैं। लगभग 11 हजार स्व-सहायता समूहों ने प्रदेश के 58 लाख से अधिक विद्यार्थियों के लिए 1 करोड़ 17 लाख गणवेश तैयार कर अपनी उद्यम क्षमता का परिचय दिया है।

मुख्यमंत्री कोविड- 19 विशेष अनुग्रह योजना

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना लागू कर पात्र दिवंगत शासकीय सेवायुक्तों के परिजनों के 188 प्रकरणों में 6 करोड़ 81 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना में अब तक दिवंगत शासकीय सेवायुक्तों के 441 पात्र परिजनों को विभिन्न पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दी गई है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपने संबोधन के पूर्व परेड का निरीक्षण किया । मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा संबोधन के उपरांत प्रदेश पुलिस के पदक विजेता अधिकारियों को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए पदक वितरित किए । मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा परेड कमांडर एवं प्लाटून कमांडरों का परिचय प्राप्त किया गया ।

(पृष्ठ 1 का शेष)

सहकारी बैंकों में सुधार की गतिविधियों...

सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया ने शिवपुरी सहकारी बैंक में पाई गई गड़बड़ी का उल्लेख करते हुए कहा कि इस घटना पर विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी। इस घटना को ध्यान में रखते हुए सभी केन्द्रीय बैंक इस बात को सुनिश्चित कर लें कि कहीं भी गड़बड़ी नहीं हो, गड़बड़ी है तो तुरंत कार्यवाही करें।

बैठक में एसीएस सहकारिता श्री अजीत केसरी ने कहा कि सहकारी बैंकों को भी दूसरे सामान्य बैंकों की तरह गतिविधियाँ संचालित करना चाहिये। उन्होंने कहा कि बैंक हैं, तो बैंकिंग की गतिविधियाँ होना चाहिये। बैंक के कर्मचारियों को बैंकिंग बिजनेस से जनरेट राजस्व से वेतन दिया जाता है। कुछ बैंकों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह बैंक बहुत घाटे में हैं। इनकी बहुत कमजोर स्थिति है। यह बैंक सुधार लायें। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों को मॉडर्न बैंक बनाने की टाइम लाइन तय करें। बैठक में आयुक्त सहकारिता एवं प्रशासक अपेक्स बैंक श्री नरेश पाल कुमार, अपेक्स बैंक के एमडी श्री पी.एस. तिवारी, सहकारिता संयुक्त आयुक्त श्री अरविन्द सिंह सेंगर, बैंक के सलाहकार श्री अखिलेश श्रीवास्तव (से.नि.आई.ए.एस.), वि.क.अ.श्रीमती अरुणा दुबे, सहायक महाप्रबंधक श्री आर.एस.चंदेल, वि.क.अ.श्री अरविंद बौद्ध, प्रबंधक श्री विनोद श्रीवास्तव, उप प्रबंधक सर्वश्री विवेक मलिक, आर.व्ही.एम.पिल्लई, करुण यादव, समीर सक्सेना, अरविंद वर्मा एवं जी.के. अग्रवाल के साथ सभी जिलों के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के सीईओ उपस्थित थे।

शिल्पियों को रोजगार के बेहतर अवसर मुहैया कराएगी राज्य सरकार -ग्रामोद्योग मंत्री श्री भार्गव

आठ राज्यों के हैण्डलूम उत्पाद एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगे

भोपाल। लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि प्रदेश में कुटीर एवं ग्रामोद्योग से जुड़े शिल्पियों को रोजगार के बेहतर अवसर मुहैया कराये जाएगें। इसके लिए मध्यप्रदेश सरकार, भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित कर स्पेशल मेले और एक्सपो आयोजित कर रही है। उन्होंने यह बात गौहर महल परिसर में आयोजित किए जाने वाले "स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो" 2021 के शुभारंभ अवसर पर कहीं। यह एक्सपों 16 अगस्त से 29 अगस्त 2021 तक आयोजित किया जा रहा है।

मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा खादी को अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाने की अपील देशवासियों से की है। खादी शहरी और ग्रामीण अंचल में रोजगार का सशक्त माध्यम बन सकती है। इसी भाव से राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का जो लक्ष्य निर्धारित किया है। उसके लिए एक जिला-एक उत्पाद का चयन कर उसके संरक्षण और संवर्धन का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हुनर की कमी नहीं है। आवश्यकता बैहतर संसाधन मुहैया कराकर परिष्कृत किए जाने की है। उन्होंने कहा कि हम सब जानते है कि मध्यप्रदेश के चंदेरी और महेश्वर में बनी साड़ियाँ, भोपाल में बने जरी जरदोजी पर्स एवं जूट के उत्पाद, धार जिले में बाघ प्रिंट, सिहोर व श्योपुर के लकड़ी के खिलौने, मंडला जिले में गौंड पेन्टिंग आदि एसे उत्पाद जिन्हें स्थानीय कलाकारों ने अलग पहचान दिलवाई है। मंत्री श्री भार्गव ने एक्सपों में आए अन्य राज्यों के दुकानदार शिल्पियों से चर्चा भी की।

इस अवसर संत रविदास हस्तशिल्प विकास निगम के प्रबंध संचालक श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव ने बताया कि कोविड महामारी के चलते बुनकरों को आई समस्याओं के निराकरण हेतु विकास आयुक्त (हाथकरधा) वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश शासन तथा संत रविदास म.प्र. हस्तशिल्प एवं हाथकरधा विकास निगम भोपाल के "मृगनयनी एम्पोरियम" के द्वारा देश-प्रदेश के बुनकरों को विपणन सहायता उपलब्ध कराने के लिए स्पेशल हैण्डलूम एक्सपों का आयोजन किया जा रहा है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि देश के प्रमुख उत्कृष्ट उत्पाद भोपाल की जनता को उपलब्ध हो सकेगें। एक्सपो में म.प्र. उत्तरप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली सहित अन्य राज्यों के बुनकरों द्वारा 56 स्टॉल लगाए गये है।

सहकारी संस्थाओं के विकास में नेतृत्व की अहम भूमिका - श्रीमती मीना डाबर

खण्डवा। राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केन्द्र, नई दिल्ली एवं जिला सहकारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में खण्डवा जिले की प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों के लिये तीन दिवसीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम का शुभारंभ श्रीमती मीना डाबर, उप आयुक्त सहकारिता एवं प्रभारी अधिकारी जिला सहकारी संघ खण्डवा द्वारा सरस्वती जी की मूर्ति पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलित कर किया गया। श्रीमती मीना डाबर ने कहा व्यक्ति प्रदेश समाज व देश के सर्वांगीण विकास के लिए संस्थाओं को अपने दायित्वों और अधिकारों को समझते हुए आगे आकर प्रभावी प्रयास करने होंगे। सहकारी संस्थाओं के विकास में नेतृत्व की अहम भूमिका होती है। सहकारी संस्था के निर्माण के लिये सबका सहयोग एवं समर्थन आवश्यक है । संस्था के गठन के पश्चात सतत् रूप से मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से आमंत्रित इन्दौर दुग्ध संघ के संचालक श्री महेन्द्र चौधरी ने इस अवसर पर कहा कि सहकारिता एक सामाजिक, आर्थिक एवं जनकल्याणकारी आंदोलन है, इसे कुशल नेतृत्व से प्रगति की ओर ले जाना है । सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर के पूर्व प्राचार्य श्री निरंजन कसारा द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने तथा सदस्यों के नेतृत्व क्षमता में वृद्धि एवं संचालित योजनाओं पर सुझाव दिया। श्री के. एल. राठौर, पूर्व प्राचार्य, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर ने बताया कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य समितियों के सदस्यों की नेतृत्व क्षमता में निखार लाने, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार कर लाभ का व्यवसाय बनाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। इन्दौर दुग्ध संघ के जिला प्रबंधक श्री कमल यादव ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले सदस्यों के लिए कार्यदक्षता में वृद्धि करना, संस्थाओं में गुणात्मक सुधार करना तथा वर्तमान परिवेश में सहकारी संस्थाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने एवं दुर्गामी परिणाम देने के लिए उक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता है। डॉ. ए.के. पटेरिया, उप संचालक पशु चिकित्सा विभाग एवं डॉ. नीरज कुमुद , पशु विभाग द्वारा शासन की लाभदायी योजनाओं पर तथा पशु बीमा, पशु टीकाकरण, पशुआहार पर विस्तृत रूप से जानकारी दी गई । दुग्ध शीतकेन्द्र खण्डवा के प्रबंधक श्री के.सी. कराहे, श्री अश्विन दुबे द्वारा कुशल नेतृत्व एवं प्रबंधन तथा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने, पशुपालन, पशु को होने वाली बीमारी से बचाव एवं उपचार पशु आहार, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि तथा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं पर मार्गदर्शन दिया गया दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के पदाधिकारियों को इन्दौर दुग्ध सहकारी शीतकेन्द्र खण्डवा का भ्रमण कराया गया एवं सांची दुध का पाश्चुरीकृत सैमपलिंग, बैंकिंग किस तरह से किया जा रहा है।

मशीनरी एवं प्लांट, लेब मशीनों आदि का भ्रमण कराया गया ।

कार्यक्रम में संचालक श्री महेन्द्र चौधरी ने प्रशिक्षार्थियों की समस्याओं के समाधान हेतु शीर्ष स्तर से पूर्ण करने का आश्वासन भी दिया। श्री संजय जैन, शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक कृषि खण्डवा द्वारा भी दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के पदाधिकारियों को बैंक से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी गई उपस्थित प्रशिक्षणार्थी को समूह चर्चा के दौरान पूछे सवालों का निराकरण किया गया। कार्यक्रम में प्रशिक्षणार्थी को अथितियों द्वारा पुरस्कार वितरण भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन जिला सहकारी संघ खण्डवा के प्रबंधक श्री मेहताबसिंह भदौरिया एवं आभार श्री निरंजन कसारा, पूर्व प्राचार्य सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर ने किया ।

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाओं के संचालकों हेतु नेतृत्व विकास प्रशिक्षण आयोजित

धार | राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केन्द्र, नई दिल्ली एवं जिला सहकारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में धार जिले की प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों के लिये तीन दिवसीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त सहकारिता श्री परमानंद गोंदरिया के मुख्य आतिथ्य किया गया । सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर के पूर्व प्राचार्य श्री निरंजन कसारा द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने तथा सदस्यों के नेतृत्व क्षमता में वृद्धि एवं संचालित योजनाओं पर सुझाव दिया। श्री के. एल. राठौर, पूर्व प्राचार्य, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर ने बताया कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य समितियों के सदस्यों की नेतृत्व क्षमता में निखार लाने, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार कर लाभ का व्यवसाय बनाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। इन्दौर क्षेत्रीय दुग्ध सहकारी संघ के प्रभारी महाप्रबंधक श्री ओ. पी . झा भी कार्यक्रम में उपस्थित थे।

रतलाम जिले में अंकेक्षको के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित

रतलाम । जिला सहकारी संघ मर्यादित रतलाम द्वारा सहकारिता विभाग के अंकेक्षको के लिए कुशलता एवं दक्षता में सुधार लाने के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन जिला मुख्यालय पर किया गया, शिविर में उपायुक्त सहकारिता सुनील कुमार सिंह ने विचार व्यक्त करते हुए कहा की सहकारी विधान अनुसार कार्य कर रही है या नहीं उसका हिसाब-किताब सही तरीके से संधारित किया जा रहा हैं या नहीं संस्थाओं के वित्तीय पत्रक संस्था की सही स्थिति दर्शा रहे है या नहीं यह सब अंकेक्षण से ही संभव हैं इसलिए अंकेक्षको को सतर्क रहकर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार अंकेक्षण करना चाहिए। वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक मुकेश भटनागर द्वारा सहकारी विधान की अंकेक्षण से संबंधित विभिन्न धाराओं का उल्लेख करते हुए अंकेक्षण की प्रक्रिया पर विस्तार से प्रकाश डाला प्रशिक्षण का संचालन जिला सहकारी संघ के श्री अनुरूद्व शर्मा द्वारा किया गया।

भारतीय राष्ट्रीय संघ की नई पहल NCUI हाट की स्थापना

नई दिल्ली । भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के अध्यक्ष श्री दिलीप संघानी ने हाट का उद्घाटन एनसीयूआई परिसर मे किया | इस हाट में राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संघों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, सरकार के प्रतिनिधि और गैर सरकारी संगठन, दिल्ली क्षेत्रों के स्थानीय निवासी NCUI हाट के उद्घाटन समारोह में भाग लिया | इस हाट का उद्देश्य पूरे भारत के स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों के उत्पादों के लिए प्रदर्शनी के माध्यम से बिक्री मंच प्रदान करना है।

इस कार्यक्रम मे एनसीयूआई शाषी परिषद के सदस्य श्री चंद्र पाल सिंह यादव, श्री बिजेंद्र सिंह, श्री अरुण तोमर, श्री जीना पोत्संगबम, श्री योगेंद्र कुमार, श्री मनीष , श्री तरुण भार्गव इफको के प्रतिनिधि , एनसीडीसी के प्रतिनिधि श्री आर. वनिता, पूर्व मुख्य कार्यकारी श्री एन सत्यनारायण सहित अन्य भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

एनसीयूआई हाट परिसर में असम, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा आदि राज्यों की सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूह को हाट में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने एवं बेचने के लिए आमंत्रित किया गया।

एनसीयूआई हाट के विचार पर विस्तार से बताते हुए श्री संघानी ने बताया कि यह छोटा कदम "सहकार से समृद्धि" की ओर ले जा सकता है। हम इस मॉडल को पूरे देश में दोहराएंगे जिससे सहकारिताओं के लिए एक विश्वसनीय मार्केटिंग नेटवर्क और उपभोक्ताओं को एक गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्रदान करेगा । श्री संघानी ने नए मंत्रालय के गठन के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। एनसीयूआई सरकार के साथ मिलकर आगे बढ़ने का संकल्प करती है । एनसीयूआई देश के सभी हिस्सों में अपनी पहुंच बढ़ाकर "वोकल फॉर लोकल" करने की सरकारी नीति के अनुसार काम करेगा। एनसीयूआई सहकारी समितियों के माध्यम से सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने का कार्य करेगा, ताकि इसका लाभ समाज के सबसे निचले और सबसे वंचित वर्गों तक पहुंचे।

कृभको के अध्यक्ष एवं एनसीयूआई के पूर्व अध्यक्ष डॉ. चंद्र पाल सिंह यादव ने कहा कि सहकारिता हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सबसे अच्छा माध्यम है। उन्होंने कहा कि कुछ सहकारी उत्पाद बहुराष्ट्रीय उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं , लेकिन उनकी मार्केटिंगअच्छी नहीं होने के कारण, उन्हें वह पहचान नहीं मिल पा रही है। एनसीयूआई हाट की स्थापना से सहकारी समितियों के उत्पादों को एक नयी पहचान मिलेगी।

नेफेड के अध्यक्ष डॉ. बिजेंद्र सिंह ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि सहकारी समितियों के पास अनेकानेक गुणवत्तायुक्त उत्पाद हैं , लेकिन विपणन के संबंध मे बेहतर प्रचार-प्रसार नहीं होने के कारण उत्पाद की बिक्री अपेक्षाकृत नहीं हो रही हैं। उन्होंने मीडिया से ज़ोर देते हुये कहा कि इस हाट की जानकारी जन –जन तक पहुचाने मे मदद करे।

डॉ सुधीर महाजन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने एनसीयूआई हाट की अवधारणा को समझाया और कहा कि यह केवल एक हाट नहीं है बल्कि एक विचार है जो सहकारिता आंदोलन में क्रांति ला सकता है। इसके सफल होने पर कमजोर सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों के लाभ के लिए देश के सभी हिस्सों में इसकी शुरुआत की जायेगी।

महाजन ने कहा कि हम निफ्ट जैसे विशेषज्ञों से उनके उत्पादों के मानकीकरण के लिए जुड़ रहे हैं। हालांकि छोटी सहकारी समिति / स्वयं सहायता समूहों में काम करने वाले लोगों ने अद्भुत उत्पादों का उत्पादन किया है, लेकिन मार्केटिंग अच्छी नहीं होने के कारण वे अपने उत्पादों का प्रदर्शन/ बिक्री नहीं कर पा रहे हैं इसलिए यह हाट उन्हें एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगा।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल में ध्वजारोहण

प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन ने अधिकारियों कर्मचारियों को दी शुभकमनाएं

भोपाल। 75 वें स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल के प्रांगण में ध्वजारोहण किया । इस दौरान संघ के समस्त अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रगान का सामूहिक गायन किया गया। सामूहिक राष्ट्रगान के उपरांत प्रबंध संचालक के द्वारा संघ अधिकारी/ कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकमनाएं दी।

अपेक्स बैंक में ध्वजारोहण

भोपाल । 75 वें स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर अपेक्स बैंक भोपाल के टी.टी. नगर स्थित मुख्यालय भवन के प्रांगण मे बैंक के प्रशासक आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें, (म.प्र.) श्री नरेश पाल कुमार ने ध्वजारोहण किया।

इस अवसर पर बैंक के प्रबंध संचालक, श्री पी.एस.तिवारी के साथ बैंक के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी श्रीमती अरूणा दुबे, श्री यतीश त्रिपाठी, सहायक महाप्रबंधक श्री आर.एस चंदेल, श्री के.टी.सज्जन, वि.क.अ. श्री अरविंद बौद्ध, प्रबंधक श्रीमती ज्योति उपाध्याय, श्री विनोद श्रीवास्तव, उप प्रबंधक सर्वश्री विवेक मलिक, आर.व्ही. एम.पिल्लई, करुण यादव, समीर सक्सेना, अरविंद वर्मा, जी.के.अग्रवाल, सहित बैंक के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित हुए।

बैंक प्रबंधन, वसूली एवं ऋण के विधिक प्रावधान पर नागरिक सहकारी बैंकों के प्रबंधक/मुख्य कार्यपालन अधिकारियों का प्रशिक्षण संपन्न

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल द्वारा नागरिक सहकारी बैंकों के प्रबंधक/ मुख्य कार्यपालन अधिकरियों को बैंक प्रबंधन, वसूली एवं ऋण के विधिक प्रावधान विषय पर दो-दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 17.08.2021 से 18.08.2021 एवं दिनांक 24.08.2021 से 25.08.2021 तक आयोजित किए गये ।इस कार्यक्रम पर विस्तृत जानकारी देते हुये श्री संजय कुमार सिंह , राज्य सह.शि.अ. ने बताया की नागरिक सहकारी बैंकों के प्रबंधक/ मुख्य कार्यपालन अधिकरियों को वर्तमान परिदृश्य मे विभिन्न ऋण, समय-समय पर की जाने वाली कार्यवाही, ऋण योजना के प्रारूप एवं प्रारूपों में किये जाने वाले संशोधन की आवश्यकता विषय पर श्री पी.के.एस. परिहार, पूर्व प्रबंधक, अपेक्स बैंक द्वारा जानकारी दी, श्री एल.डी.पण्डित, पूर्व महाप्रबंधक अपेक्स बैंक द्वारा नागरिक सहकारी बैंको में ऋण सम्पत्ति, नागरिक सहकारी बैंकों में गंभीर अनियमितताओं के प्रकरण, एन. पी. ए . कम करने के उपाय एवं टेक्निकल राइट्स ऑफ, नागरिक सहकारी बैंकों मे वसूली प्रबंधन , कालातीत ऋणों की वसूली विषय पर जानकारी दी। श्रीमती फ्लोरा नाम्बियार, सी.बी.आई. ने मापदण्ड निवेश नीति, सी.आर.आर. एवं एस.एल. आर. का प्रबंधन पर जानकारी दी । आर.बी.आई. को भेजे जाने वाले रिटर्न्स एवं उनका परीक्षण(आयकर, CGST, SGST), आर.बी.आई. निरीक्षण में मिलने वाली सामान्य कमियॉ एवं उनका निराकरण विषय पर सुश्री सौम्य कोड़ती, सहा. प्रबन्धक, श्री लालचंद भोयर, सहा. प्रबन्धक, श्री पराग सान्दुगुले, प्रबन्धक आर.बी.आई. के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कार्यक्रम का समन्वय श्री संतोष येडे, राज्य समन्वयक, श्री जी.पी. मांझी, प्र.प्राचार्य एवं श्रीमती मीनाक्षी बान, कम्प्यूटर प्रशिक्षक द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम मे श्री धनराज सैदान्णे, श्री लोकेश श्रीवास्तव, श्री ज्ञानू सिंह का विशेष सहयोग रहा |

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।